

पांच साल में एपीआई में आत्मनिर्भर होंगे हम, फिलहाल चीन 35 फीसदी सस्ता बना रहा

भास्कर इंटरव्यू

फार्मा इंडस्ट्री पर कोविड का सकारात्मक असर देखा गया। आरएंडडी बढ़ी है और सरकारें तत्परता से नियामकीय मंजूरियां दे रही हैं। इस बीच भारतीय फार्मा इंडस्ट्री ने ताकत दिखाई, लेकिन एपीआई इसकी कमजोरी रही है। इन्हीं मसलों पर दैनिक भास्कर के भीम सिंह ने इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल सुदर्शन जैन से बात की। पेश है प्रमुख अंश...

• अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय फार्मा कंपनियों का कितना दखल है?

भारत दुनिया की करीब 20 फीसदी दवाओं की आपूर्ति करता है। अमेरिका में एक तिहाई और यूरोप में एक चौथाई दवाओं की आपूर्ति भारतीय कंपनियां करती हैं।

• कोविड महामारी के चलते भारतीय फार्मा इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए? फार्मा कंपनियों और सरकार के बीच सहयोग बढ़ना सबसे बड़ा बदलाव है। मेडिकल प्रोडक्ट्स का इमर्जेंसी

यूज अथॉराइजेशन और वॉलंटरी लाइसेंसिंग शुरू हुई। कोविड वैक्सीन इसका उदाहरण है। सरकार फार्मा इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम भी लेकर आई।

• भारत फार्मा प्रोडक्ट्स का बड़ा निर्यातक है, लेकिन करीब 70% एपीआई का आयात करता है। ऐसा क्यों? 1980 के दशक में भारत में 80% तक एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ट्रेडिगेंट (एपीआई) की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। बाद में चीन ने इसे बहुत बढ़ावा दिया। वहां 4-5% ब्याज पर लोन मिल रहा है, जबकि भारत में 12-13% ब्याज है। वहां बिजली की लागत भारत से आधी है। चीनी सरकार मुफ्त में

जमीन भी देती है। इसके चलते चीन में एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग लागत भारत से 30-35% कम है। जाहिर है, आयात सस्ता पड़ रहा है।

• तो क्या एपीआई के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी? जरूर आएगी। सरकार एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रही है। हमारा अनुमान है कि अगले पांच साल में हम एपीआई के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

• फार्मा इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है? भारतीय फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर अभी करीब 43 अरब डॉलर का है। हमारा अनुमान है कि इस दशक के अंत तक टर्नओवर 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।



सुदर्शन जैन
सेक्रेटरी जनरल, आईपीए